दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 01 फरवरी 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 125

महत्वपूर्ण एवं खास

वस्त्र उद्योग में भारत की क्षमताओं को पुन: मजबूत बना रही है सरकार

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए 4500 करोड़ रुपये के निवेश से सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और ऐपेरल पार्क बनाये जा रहे हैं, जिससे देश में उत्पादन की समन्वित श्रंखला का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा। कोविंद संसद के बजट अधिवेशन के प्रारंभ में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी सरकार नये क्षेत्रों के साथ-साथ उन पारंपरिक क्षेत्रों में भी देश की स्थिति को पुन: मजबूत बना रही है, जिनमें हमारे पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव है। इसी दिशा में मेरी सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4500 करोड़ रुपये के निवेश से सात मेगा समन्वित वस्त्र क्षेत्र और परिधान उद्योग-पार्क बनाए जा रहे हैं। कोविंद ने कहा, इससे देश में एक समन्वित वस्त्र मूल्यवर्धन श्रृंखला तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये मेगा वस्त्र उद्योग पार्क भारतीय निवेशकों के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भी अकर्षित करेंगे तथा रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे।

रेल हादसे में अलग अलग स्थान पर दो मौत

करमा/सोनभद्र (आरएनएस)। स्थानीय थाना अंतर्गत करमा गेट के पास व खम्भा नम्बर 182/7 भैरोपुर सडक़ के नजदीक सागौन के पास बीते रविवार को देर रात करीब 8 बजे रेलवे हादसे में दो की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय कुमार 30 वर्ष पुत्र रामसजीवन निवासी करकी माइनर (पांपी) सन्दिग्ध अवस्था में रेलवे ट्रैक पर बीती रात आठ बजे मालगाड़ी से कट गया। स्थानीय लोगों व उसके प प्रतिशती के सबिता के अनुसार दोपहर 2 बजे घर से निकलने के बाद घर पर नहीं आये। पिता रामसजीवन ने बताया कि हम अपने ससुराल नौगढ़ से रात में घर आये तो चट्टी पर रेलगाड़ी से कटने कि चर्चा हो रही थी तब तक पुलिस की गाड़ी आगयी और मेरे घर के पीछे 82 खंभे को पूछताछ करने लगे ,फिर स्टेशन मास्टर से बातचीत में पता चला कि खम्भे नम्बर 182/7 की घटना है। कुछ देर बाद पता चला कि मेरे बेटे विजय की है।इतना सुन घर में कोहराम मच गया।प प्रतिशती का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों ने बताया कि विजय को 5 लड़कियां, एक लडक़ा 3माह का है। विजय का शव नग्न अवस्था में पास में दो शराब की बोतल पड़ी थी। पुलिस शव को कबजे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गयी।

मशहूर मॉडल ने होटल की छठी मंजिल से लगा दी छलांग

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान के जोधपुर में मॉडल गुनगुन उपाध्याय ने रातानाडा के होटल की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। सुसाइड करने से पहले उसने अपने पिता को फोन किया और उन्हें इसकी जानकारी दी। हालांकि, नीचे गिरने के बाद गुनगुन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण गुनगुन की पसलियों व पैर में फ्रेक्चर आया है। हालांकि, उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने बताया कि गुनगुन शनिवार को उदयपुर से जोधपुर आई थीं। वह यहां के रातानाडा के होटल में रुकीं थीं। रविवार को उन्होंने अपने पिता को फोन किया। कहा कि पापा मैं सुसाइड करने जा रही हूं, बस मेरा चेहरा देख लेना। इसके बाद पिता गणेश उपाध्याय ने पुलिस से संपर्क किया। एसीपी देरावर सिंह ने फोन नंबर के आधार पर गुनगुन की लोकेशन ट्रैस की और घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि, तब तक गुनगुन छठी मंजिल से छलांग लगा चुकी थी। पुलिस ने बताया कि मॉडल को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि गुनगुन का काफी खून बह चुका है, इसलिए फिलहाल वह बात करने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही उसे होश आएगा, पूछताछ की जाएगी। हालांकि, अभी तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि गुनगुन के पिता गणेश उपाध्याय जोधपुर में ही मंडी व्यवसायी हैं। फिलहाल, उनसे गुनगुन के बारे में पूछताछ की जा रही है।

उत्तराखंड सरकार लिखे वाहन से स्मैक बरामद

हरिद्वार (आरएनएस)। एसटीएफ ने उत्तराखंड सरकार लिखे वाहन से स्मैक के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक बरेली से लाई जा रही थी। स्मैक की कीमत बाजार में सात लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसटीएफ के एसएएपी अजय सिंह ने बताया कि टीम ने चंडीघाट बैरियर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नजीबाबाद की ओर से आ रही लाल रंग की कार की तलाशी ली गई। कार सवार तीन युवकों के कब्जे से 95 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने स्वयं को आलम पुत्र शमीम निवासी ग्राम रायपुर भगवानपुर, हारून पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला किला कस्बा मंगलौर और अमजद पुत्र शमशेर निवासी कस्बा पिरान कलियर बताया।

बजट अनुमान 2021-22 सरकार के सामाजिक सेवा क्षेत्र के आवंटन में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है

नईदिल्ली (आरएनएस)। वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार महामारी के दौरान सामाजिक सेवाओं पर सरकार के खर्च में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में सामाजिक सेवा क्षेत्र के व्यय आवंटन में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सामाजिक क्षेत्र व्यय- आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 2021-22 (बजट अनुमान) में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च के लिए कुल 71.61 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए थे। पिछले वर्ष (2020-21) का संशोधित व्यय बजट राशि से बढक़र 54,000 करोड़ रुपये हो गया। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2021-22 (संशोधित अनुमान) में इस क्षेत्र के कोषों में सकल घरेलू उत्पाद का 8.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2020-21 (बजट अनुमान) में यह 8.3 प्रतिशत थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत रहा। यह 2021-22 (बजट अनुमान) में 26.6 प्रतिशत था।

आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय 2019-20 के 2.73 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 (बजट अनुमान) में बढक़र 4.72 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस तरह इसमें लगभग 73 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। समीक्षा में कहा गया है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए समान अवधि में यह वृद्धि 20 प्रतिशत की रही।

शिक्षा- महामारी पूर्व वर्ष 2019-20 जिसके लिए डाटा उपलब्ध है, के मूल्यांकन से पता चलता है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक को छोडक़र 2018-19 और 2019-20 के बीच मान्यता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूलों में पेय जल तथा स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन तथा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दिए जाने से आवश्यक संसाधन प्रदान किए गए और स्कूलों में परिसंपत्ति का सृजन हुआ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 19/01/2022 तक 8,39,443 स्कूलों को नल से जल आपूर्ति की गई। 2012-13 से 2019-20 तक निरंतर रूप से सभी स्तरों पर शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोडऩे की दर में गिरावट आई। 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोडऩे का प्रतिशत 1.45 प्रतिशत रहा, जबकि यह 2018-19 में 4.45 प्रतिशत था। यह गिरावट लडक़ों और लड़कियों दोनों के लिए रही। इस गिरावट से पिछले दो वर्षों में पढ़ाई छोडऩे के प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति के विपरीत है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में सभी स्तरों पर सकल

नामांकन अनुपात (जीईआर) और लैंगिक समानता में भी सुधार हुआ। वर्ष 2019-20 में स्कूलों में 26.45 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ। इससे 2016-17 और 2018-19 के बीच जीईआर में गिरावट की प्रवृत्ति में कमी लाने में मदद मिली। वर्ष के दौरान स्कूलों में लगभग 42 लाख अतिरिक्त बच्चों का नामांकन किया गया, जिसमें से 26 लाख बच्चे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के थे और एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसएफ+) के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के अनुसार पूर्व प्राथमिक में 16 लाख बच्चों का नामांकन किया गया।

2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन अनुपात 27.1 प्रतिशत रहा, जोकि 2018-19 के 26.3 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि सरकार ने उच्च शिक्षा इको-सिस्टम को क्रांतिकारी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं इन कदमों में नेशनल एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना में संशोधन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ई-पीजी पाठशाला, उन्नत भारत अभियान तथा कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति शामिल हैं।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली पर महामारी का महत्वपूर्ण असर हुआ, जिससे भारत के स्कूलों और कॉलेजों के लाखों लोग प्रभावित हुए। समीक्षा में कहा गया है कि बार-बार लगाए जाने वाले लॉकडाउन के कारण शिक्षा क्षेत्र पर रियल टाइम प्रभाव का पता लगाना कठिन है क्योंकि नवीनतम उपलब्ध व्यापक आधिकारिक डाटा 2019-20 का है। इसमें शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट (एएसईआर) 2021 की चर्चा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र के लिए महामारी के दौरान प्रभाव का आकलन किया गया है। एएसईआर में यह पाया गया कि महामारी के बावजूद 15 से 16 वर्ष की आयु में नामांकन में सुधार जारी रहा, क्योंकि नामांकित नहीं किए गए बच्चों की संख्या 2018 में 12.1 प्रतिशत से कम होकर 2021 में 6.6 प्रतिशत रह गई, लेकिन एएसईआर रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि महामारी के दौरान स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के वर्तमान में नामांकित नहीं किए गए बच्चों का प्रतिशत 2018 के 2.5 प्रतिशत से बढक़र 2021 में 4.6 प्रतिशत हो गया। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि स्कूली बच्चों, उनके विषय तथा रिसर्च शेयरिंग की पहचान करने के लिए सरकार ने कोविड-19 कार्य योजना राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की है।

हिमाचल: मेडिकल कॉलेजों में एक सप्ताह तक सामान्य ऑपरेशनों पर रोक

शिमला (आरएनएस)। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रुटीन आपरेशन पर रोक लगा दी है। कोरोना के चलते फिलहाल एक सप्ताह तक यह व्यवस्था की गई है। मामले घटने के बाद ही सर्जरी, पथरी, आर्थोपेडिक्स, आंखों के ऑपरेशन हो सकेंगे। हादसों में घायल व गंभीर रोगियों के ऑपरेशन चलते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एक्टिव मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी भी प्रतिदिन कोरोना के मामले दो हजार आ रहे हैं।

अस्पतालों में भीड़ होने पर ही लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अस्पताल परिसरों और ओपीडी में भीड़ न एकत्र करने और वार्डों में भी मरीजों के पास एक से ज्यादा तीमारदार न होने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी शिमला, कांगड़ा के टांडा, हमीरपुर, चंबा, नाहन और मंडी नेरचौक में मेडिकल कॉलेज हैं। डॉक्टरों को भी रुटीन के ऑपरेशनों की तिथियां फिलहाल नहीं देने के लिए कहा है।

प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 95 सौ के करीब है, जबकि मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तक प्रदेश में 3969 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अस्पतालों में 40 मरीज ऐसे हैं, जिनकी हालत गंभीर है। इन्हें आईसीयू पर रखा गया है, जबकि ऑक्सीजन बेड पर भी 50 के करीब मरीज हैं। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन लोग लापरवाह हो रहे हैं। अस्पतालों में रूटीन ऑपरेशन को अभी बंद रखा गया है।

बिना मास्क के अस्पतालों में प्रवेश नहीं

प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों को इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा है।

महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है: कोविंद

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपतिने कहा

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज यहां संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर और समान भागीदारी प्रदान करने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाएं तेजी से महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। 2021-22 में बैंकों ने 28 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 65,000 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी है। यह 2014-15 में बढ़ाई गई राशि का चार गुना है। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के हजारों सदस्यों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें बैंकिंग सखी के रूप में भागीदार भी बनाया है। ग्रामीण परिवारों तक ये महिलाएं घर द्वार जाकर बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हम सभी उज्ज्वला योजना की सफलता के साक्षी हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं व बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा दिया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल के कई सकारात्मक परिणाम मिले हैं और स्कूलों में नामांकित लड़कियों की संख्या में उत्साहजनक सुधार हुआ है। मेरी सरकार ने बेटे-बेटियों को बराबर मानते हुए पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए विधेयक भी पेश किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाकर समाज को इस मनमानी प्रथा से मुक्त कराने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं के केवल मेहरम के साथ हज करने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। 2014 से पहले अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग तीन करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी जबकि मेरी सरकार ने 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। इससे मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोडऩे की दर में उल्लेखनीय कमी आई है और उनके नामांकन में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर समावेशी कोष (जेंडर इनक्लूजन फंड) का भी प्रावधान किया गया है। यह खुशी की बात है कि सभी मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों में छात्राओं का दाखिला शुरू हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स के प्रवेश को भी मंजूरी दे दी है। महिला कैडेट्स का पहला जत्था जून 2022 में एनडीए में प्रवेश करेगा।

कानपुर में इलेक्ट्रिक बस हादसे में 6 लोगों की मौत, 9 गंभीर

- टाटमिल चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस ने 17 वाहनों को रौंदा, राष्ट्रपति ने जताया शोक

कानपुर (आरएनएस)। कानपुर में रविवार देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। टाटमिल चौराहे पर एक इलेक्ट्रिक बस ने 17 वाहनों को रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई,जबकि 9 की हालत नाजुक है। बस वाहनों को टक्कर मारते हुए चौराहे पर बने ट्रैफिक बूथ से टकराकर हुए डंपर में घुस गई। पुलिस ने सभी घायलों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बस ने 2 कार,10 बाइक व स्कूटी, 2 ई-रिक्शा और 3 टेंपो में टक्कर मारी।

भीड़ जुटती देख ड्राइवर बस से कूदकर भाग निकला। पुलिस ने हादसा करने वाले बस ड्राइवर को 11 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी (पूर्वी) प्रमोद कुमार ने बताया कि सिटी बस संख्या यूपी 78 जीटी 3970 से यह हादसा हुआ। बस को सत्येंद्र कुमार चला रहा था,जो कि हादसे के बाद से भाग निकला था। सिटी बस सेवा के मैनेजर संचालन डीवी सिंह ने बताया कि हादसों के कारणों की पूछताछ की जा रही है।

हादसे में लाटूश रोड पर रहने वाले शुभम सोनकर (26),ट्विंकल सोनकर (25), बेकनगंज में रहने वाले अरसलान (24),नौबस्ता केशव नगर निवासी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अजीत कुमार (62),रामपुरम श्याम नगर निवासी रिक्शा चालक कैलाश (48) और शुक्लागंज निवासी रमेश (47) की मौत हो गई।

हादसे में मृतकों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा

वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद कमिश्नर डॉ.राजशेखर हैलट अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने प्राचार्य डॉ.संजय काला को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए।बस हादसे में डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि कि हादसे में मृतकों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बस की जांच के लिए टेक्निकल कमेटी गठित की गई है। फ़ोटो और वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरे मामले की जांच की जा रही है।

इस हादसे में धनकुट्टी के व्यापारी दिनेश शुक्ला,उनके बहनोई राजेश त्रिपाठी, दिनेश की प प्रतिशती आरती अंजली मिश्रा, बहन नीलू त्रिपाठी समेत 9 लोग घायल हो गए। दिनेश कार में बैठे थे और राजेश उसे चला रहे थे। दिनेश समेत परिवार के सभी सदस्यों को कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रतापगढ़ के प्रताप पाल टेंपो से घंटाघर जा रहे थे। उन्हें घर जाने के लिए ट्रेन पकडऩी थी। इसी तरह सनिगवां के अमित कुमार और सौरभ एक बाइक से जा रहे थे। ई-बस ने बाइक में टक्कर मारी तो दोनों उछलकर दूर जा गिरे।

सौरभ की हालत गंभीर बताई जा रही है। झकरकटी निवासी जीतराम घंटाघर जा रहे थे। बस ने उन्हें भी चपेट में ले लिया। अमित अंडे का ठेला लगाता है। दुकान बंद करने के बाद घंटाघर खाना खाने जा रहा था। सुनील, शुभम और रमेश एक ही स्कूटी पर थे। ये तीनों शादी से लौट रहे थे।

सरकार का अनुमान, एफवाई23 में 8-8.5 प्रतिशत रह सकती है जीडीपी ग्रोथ

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करेंगी और उससे पहले आज उन्होंने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस सर्वेक्षण से 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण दिया गया है। यह 2022-23 वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8 से 8.5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाता है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में 8-8.5 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ (आर्थिक वृद्धि दर) का अनुमान लगाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वैक्सीन कवरेज और सप्लाई साइड रिफॉर्म से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। सरकार का जीडीपी अनुमान इस बात पर आधारित है कि आगे महामारी से कोई आर्थिक गतिविधि प्रभावित नहीं होगी और मानसून भी सामान्य रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मानसून या महामारी का कोई प्रभाव आता है तो जीडीपी घट सकती है। वित्त वर्ष 2021-22 की इस आर्थिक समीक्षा में यह पता चलेगा कि कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के बीच देश ने किस तरह से तरक्की की। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में 8-8.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। ये चालू वित्त वर्ष के 9.2 प्रतिशत के ग्रोथ अनुमान से कम है। समीक्षा में कहा गया कि महामारी से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा, यह मानते हुए ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है।

राहुल गांधी 3 फ रवरी को करेंगे 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' का शुभारंभ

- भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष मिलेगी 6 हजार रुपए की मदद
- 3 लाख 55 हजार हितग्राहियों को मिलेगी प्रथम किश्त की राशि

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद 'न्याय सब्बो बर-सब्बो डहर' के ध्येय को लेकर योजनाएं लागू की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। विभिन्न वर्गों के लिए 'न्याय' की कड़ी में अब ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए 'न्याय' मिलने जा रहा है। इस योजना की शुरुआत आगामी 3 फरवरी को होगी। सांसद राहुल गांधी राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए राज्य के अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी योजना के लिए पात्र 3 लाख 55 हजार भूमिहीन कृषक मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों राशि अंतरण करेंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की आबादी में 70 फीसदी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। खेती-किसानी के कार्यों में काफी संख्या में कृषि मजदूरों जुड़े होते हैं। इनमें से कई ऐसे कृषि मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है और वे दूसरों की कृषि भूमि में श्रमिक के तौर पर काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन्हीं भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्या को समझा और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' लागू करने की घोषणा की। योजना के लिए 1 सितंबर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन किया गया। साथ ही हितग्राहियों की पहचान करने एवं उन्हें वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' का लाभ लेने के लिए अब तक 3 लाख 55 हजार हितग्राहियों ने पंजीयन कराया है।

इसलिए योजना - छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों से जुड़ा है। कृषि कार्यों में गांव में कई भूमिहीन परिवार कृषि मजदूरी का कार्य करते हैं। राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं, लेकिन रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर कम हो जाते हैं। इसमें से कई कृषि मजदूर भूमिहीन हैं, जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है। ऐसे में यह योजना भूमिहीन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी।

योजना के लिए यह होंगे पात्र - योजना के अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे। इस योजना के हितग्राहियों के लिए आवश्यक शर्त यह है कि हितग्राही परिवार के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। आवासीय प्रयोजन के लिए धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।

राज्य की एक और महत्वपूर्ण योजना - बता दें कि 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' राज्य की एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसके जरिए ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को सीधे आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने इस योजना से पहले 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' और 'गोधन न्याय योजना' लागू की हैं, जिनकी चर्चा देश-दुनिया में हो रही है। 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के जरिए किसानों को फसल विविधीकरण एवं उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में बड़ी धनराशि दी जा रही है। किसानों को ऐसी मदद देशभर में कोई भी राज्य सरकार नहीं कर रही है।

वहीं 'गोधन न्याय योजना' के जरिए राज्य के गोपालकों, किसानों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी कर उन्हें सीधा लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में खरीदे गए गोबर से गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे जैविक कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में काम हो रहा है। साथ ही कई महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा गौ-कास्ट, दीये, गमला समेत अनेक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे स्व-सहायता समूहों की महिलाओं व उनके परिवार को आर्थिक संबलता और समृद्धि मिल रही है। अब तो गोबर से बिजली उत्पादन भी शुरू हो चुका है।